7

weighed on machine found the difference by 0.25 M.T. to 16.5 M.T. costing nearly Rs. 5 lakhs:

- (b) whether it is a fact that weigh bridges in the collieries of Western Coalfields are made to remain out of order or are outdated and therefore frequent break downs occur.
- (c) whether it is also a fact that Junnar Deo Weigh bridge is operating only for half the days of the year; and
- (d) what corrective steps are being taken in this direction?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) According to information furnished by Western Coalfields Ltd., (WCL), Junnardeo weighbridge was out of order during the first four days of May, 1991. During this period loading was done on volumetric basis. WCL have stated that they are not aware of any complaint of the nature mentioned.

- (b) No, Sir. Although weighbridges do sometimes breakdown like any other machinery, their average availability is of a high order.
- (c) and (d) No, Sir. For example, in the month of May, 1991, Junnar-deo weigh-bridge was out of order for the first four days, but was functioning well for the rest of the month. WCL has taken up the matter of proper maintenance with the concerned company which maintain Junnordeo weighbridge, and have instructed it to further improve its maintenance and availability.

1035. [Transferred to 31st July, 1991]

## Lifting of ban on Japanese firms for tenders floated by I.O.C.

1036. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of PET-ROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was a ban on Japanese companies on

the participation in tenders floated by Indian Oil Corporation;

- (b) whether it is also a fact that the Government of India have lifted the ban recently; and
- (c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND): (a) Orders were issued to Public Sector Undertakings under the then Ministry of Petroleum and Chemicals in December 1989, not to give further business to the Consortium of Japanese Companies which functioned under the name of M/s. Sumitomo Corporation. These orders were withdrawn in May, 1991 after agreements between M/s. Sumitomo Corporation and PNGC/GAIL to refer their contractual dispute to arbitration.

## Increase in the number of flights between Zurich and Delhi

1037. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

- (a) whether some additional flights between Zurich and Delhi have recently been started; and
- (b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIA-TION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) and (b) Swissair was operating 7 flights a week through Bombay till 23-6-1991. However, keeping in view the traffic requirements, they have shifted three of their services to Delhi with effect from 24-6-1991.

## तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयक्षे की आपूर्ति

## 1038. डा. जिनेन्द्र कुमार जैन: सरदार जगजीत सिंह ग्ररोड़ा:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृदा करेगे कि: tai

[ 29 JULY 1991 ]

- (क) क्या यह सच है कि पर्यात माला में कोयले के उपलब्ध न हो पाने के कारण देश के कई तापीय विद्युत संयंत्र श्रपनी ग्रधिष्ठापित क्षमताका पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं ;
- (ब) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में तापीय विद्युत परियोजनाम्नों को पर्यास्त माला में कोणले की ग्राप्ति नहीं हो रहीं है:
- (ग) क्या यह भी सच है कि कोवले विभाग को य अन्देश दिए गए है कि वह इस्पात, लोको विद्युत भीर सींमेन्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर को बले की अपित करें:
- (घ) क्या यह भी सच है कि कोल इंडिया लि० ने दावा किया है कि इस समय देश में की जल का लतादन संतीष-जनक है : ग्रीर
- (ङ) क्या यह सच है कि उन्तर प्रदेश गूजरात महाराष्ट्र ग्रीर दक्षिण भारत में स्थित परियोजनाओं को कोयले को म्रापृति ध्या-समय तथा पयात्व माना में नहीं हो रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. नायमेगीडा): (क) जी, 16 ताणीय विद्युत गृहो ने अप्रेल तथा मई; 1991 की अवधि में को०ले की ग्राप्ति ग्रपर्याप्त रूप में होने के फारण बिजली के उत्पादन में कमी होने की सूचता दी है।

- (७) उपपुत्त विद्युत गृह-राजस्थान उन्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महा-राष्ट्र, ग्रांध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिल-नाड में स्थिति है।
- (ग) जी, हां। कीयला मंत्रालय कोयला कंपनियों को इस्पात लोको विद्युत तथा सीमें टक्षेत्रों को प्राथमिकता के

ग्राधार पर कोयले की ग्रापति कि**ए** जाने के निदेश जारी कर किए हैं।

- (घ) जी, हां कोल इंडिया लि॰ द्वारा किया गया कोयचे का उत्पादनहै समग्र रूप से संतोषजनक रहा। कोल इंडिया लि० के लिए वर्ष 1991-92 में 203 मि. टन कोयले से उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। अनन्तिम आंकड़ो के अनुसार इसने 1-4-91 से 30-6-91 की श्रविध के दौरान 42.633 मि० टन लक्ष्य उत्पादन की तूलना में 41.88 मि॰ टन कोंयले का उत्पादन किया, जो कि लक्ष्य उत्पादन का 98.23% है, ग्रीर यह रत्पादन पिछले वर्ष की इसी प्रविध में उत्पादित किए गए कोग्ले की तुलना में 7.2% अधिक है।
- . (ड) जबिक उत्तर प्रदेश के तापीय विध्त गही को कोयले की श्राप्ति सामा न्यतः सठतीयजनक रही, किन्तुं गुजरात महाराष्ट्र ग्राध प्रदेश कर्नाटक तथा तिमलनाडु के विद्युत गही को कोण्ले की पर्याप्त गहीं हो रही है। कोयले की अपयोप्त रूप में श्रापृति का मुख्य कारण सिगरेनी को० लियरीज कंपनी लि० आंध्र प्रदेश द्वारा कानून तथा व्यवस्था की स्थिति भ्रौर श्रीधीगिक संबंधी की समस्याश्रों के कारण कोयले का निरन्तर कम स्तर उत्पादन किए जाने के कारण है। इस कोथले कंपनी के साथ संयोजित तमिलनाड कर्नाटक, ग्रांध्य प्रदेश तया महागष्ट् के तापीय विद्युत गृहों को कोयले की स्रापृति अन्य कोण्ला कंपिनियों से करनी पडती है, जिस कार्य में रेल ग्रथवा रेल-सह-समुद्री मार्ग की लम्बी दूरी अन्नग्रंस्त है। विद्यमान लदान सुविधा वैगनों की उपल-ब्धता मार्गी की क्षमता सीमित होने के कारण कोवला कंपनियों के पान पर्याप्त माला में कोण्ला उपलब्ध होने के बाबजूद भी उपभोक्ताओं को कोयले की ग्रापृति किए जाने की कार्यवाई प्रभावित होती है।